(iv) वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण —29193 कि॰ एम॰ एस*

(v) संरचनात्मक वेधन —6 कूप (5318 मीटर)

*वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण द्वारा किए गए क्षेत्र में बिहार का भी कुछ भाग शामिल है।

अब तक उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण पर करीब 73 करोड़ रुपए का व्यय उपगत हुआ है।

(ग) उत्तर प्रदेश में सात अन्वेषण कूपों का वेधन किया गया है। तथापि, हाइड्रोकार्बन नहीं मिला है।

(घ) उत्तर प्रदेश में कोई गैस भंडार सिद्ध नहीं हुआ है।

Guidelines to Detect Spurious Gas Cylinders

2257. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the procurement cost of 14.2 Kg empty LPG cylinder and its book value after one year of its purchase;

(b) whether any list indicating the number and series of the LPG Cylinder procured by the Oil Corporation are circulated to their respective distributors/ Area Offices of the Oil Corporation;

(c) whether any criteria/guidelines have been issued by the Ministry/respective Oil Corporations to detect spurious gas cylinder;

(d) if so, the date and other details circulated to the distributors to enable them to detect the induction of such spurious cyliders in the system; and

(e) if not, the relief to be granted by the respective Oil Corporation to the honest distributors cheated by unscrupulous persons?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) The procurement cost of a 14.2 Kg cylinder comes to around Rs. 900 per cylinder inclusive of cost of value and excise duty, sales tax and freight. The cost of cylinder is zero after full capitalisation.

(b) No, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) Area oiffices controlling the distributors issue guidelines to the distributors from time to time for their education and detection of spurious cylinders.

(e) Does not arise in view of (d) above.

UNDP Aid for Forest Fires

2258. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are seeking UNDP aid for training and implementing programmes for forest fires;

(b) the quantum of aid sought from UNDP;

(c) the quantum of aid given by UNDP;

(d) how are these funds spent; and

(e) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINSTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) No, Sir.

(b) to (e) Do not arise.

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों को बाघ परियोजना में सम्मिलित किये जाने संबंधी प्रस्ताव

2259. **श्री गोविन्दराम मिरी:**
श्री नारायण प्रसाद गुप्ता:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में तीन राष्ट्रीय उद्यानों/ अभयारण्यों को बाघ परियोजना में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब तक प्रदान की जायेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) बाघ परियोजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में इस समय पांच राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत कुछ और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को शामिल करने के प्रस्ताव हैं।

(ख) चालू योजना अवधि के दौरान निधियों की कमी के कारण परियोजना पर अगली योजना अवधि के दौरान विचार किया जा सकता है।

Agreements with Malaysian Group for National Super Highways

2260. SHRI DIGVIJAY SINGH:
SHRI ANANT RAM JAISWAL:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether tenders floated for National Super Highways about feasibility has been ignored for NSH-2 before entering into agreements with a Malaysian group;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether agreement for NSH-2 is controversial as reported in Indian Express dated 2nd August, 1995; and

(d) if so, the steps taken to rectify the undue advantages proposed in the agreement?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) No agreement has been entered into with any private Malaysian group for construction of any Super National Highway.

(b) to (d) In view of (a) above, (b), (c) & (d) do not arise.

भारतीय व्यापारियों को अमरीकी वीजा प्राप्त करने में समस्या पेश आना

2261. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई वीजा प्रणाली के कारण भारतीय व्यापारियों को अमरीकी वीजा प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों के बारे में सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में अमरीकी सरकार से संपर्क कायम किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अमरीका की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) 13 जनवरी, 1995 से लागू नए अमरीकी विनियमों के कारण भारतीय व्यवसायियों के लिए समय से वीजा प्राप्त करना कठिन हो गया है। इससे उन भारतीय व्यवसायियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जो सेवा प्रदान करने के लिए, विशेषकर सोफ्टवेयर के क्षेत्र में अमरीका जाना चाहते हैं।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार ने भारत और अमरीका दोनों में ही विभिन्न स्तरों पर अमरीका की सरकार को भारत की चिन्ता से अवगत करा दिया है। इस बात पर बल दिया गया है कि इन नए नियमों से उन परियोजनाओं में विलम्ब होगा जो संविदा तथा भागीदारी के आधार पर अमरीका उद्योग के लिए भारतीय संगठनों द्वारा निष्पादित की जा रही है।

अमरीका की सरकार इस संबंध में भारत की हित-चिन्ता से अवगत है और उसे समझती है। इस मुद्दे पर विश्व व्यापार संगठन में भी चर्चा की जा रही है क्योंकि अमरीकी विनियम केवल भारत के लिए ही नहीं हैं बल्कि सभी कुशल विदेशी व्यवसायियों पर समान रूप से लागू होते हैं।

सरकार इस संबंध में गतिविधियों को ध्यानपूर्वक मानीटर कर रही है तथा इस संबंध में भारत के हितों की रक्षा के प्रति सचेत है।

Delhi-Bomaby Expressway

2262. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "Delhi-Bombay Expressway-con-